भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3247

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

“स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर घटा हुआ जीएसटी”

3247. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कर लाभ का स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कम प्रीमियम में परिलक्षित होना सुनिश्चित करने के लिए मुनाफाखोरी-रोधी उपायों को बहाल करने या सुदृढ़ करने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार की योजना स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में कमी के परिणामस्वरूप राज्यों की संभावित राजस्व क्षति का समाधान करने की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इस क्षति को उपभोक्ता राहत की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) : जीएसटी की दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी के मुद्दे को दिल्ली में 09 सितम्बर, 2024 को आयोजित जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के समक्ष रखा गया था। विस्तृत विचार-विमर्श करने के उपरांत जीएसटी परिषद ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से संबंधित मामलों को समग्र रूप से जांचने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) के गठन की सिफारिश की थी। तदनुसार, श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप-मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। मंत्री समूह (जीओएम) ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी परिषद को अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जीएसटी परिषद की किसी भी सिफारिश के अभाव में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कर लाभ पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।